राष्ट्रीय बागवानी मिशन : एक अध्ययन

• सुनील कुमार चौधरी * • डॉ. शारदा शिन्दे**

ईमेल–Choudhary_sunil@live.com

सारांश

यह शोध पत्र ''राष्ट्रीय बागवानी मिशनः एक अध्ययन'' के माध्यम से कृषि को देश की अर्थव्यवस्था के विकास की एक कुंजी के रूप में इंगित किया गया है। कृषि क्षेत्र के विविध आयामों में बागवानी कृषि की एक मुख्य शाखा है और इसका कृषि के क्षेत्र में व्यापक स्थान है, जो कृषि के विविधीकरण, पोषण–आहार की सुरक्षा और कृषि भू–भाग को विस्तृत करने के साथ ही रोजगार सृजन के चहुँमुखी अवसरो के विकल्प को संजोय हुए है अन्य देशें कि तुलना में भारत में बागवानी विकास की अनेक अनुकूल दशाएँ होने के बावजूद भी बागवानी विकास का आपेक्षित स्तर प्राप्त नही किया जा सका है लेकिन बागवानी विकास के घटको में एन.एच.एम. एक केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम प्रमुख घटक है जिसका उद्देश्य बागवानी विकास के समग्र विकास को उन्नत करना है। और विगत वर्षों में मिशन ने आपेक्षकृत लक्ष्य प्राप्ति में सफलता की प्रगति भी प्राप्त की है।

राष्ट्रीय बागवानी मिशन के विभिन्न पक्षों पर यह शोध पत्र केन्द्रित है, जिसमें मिशन की प्रगति की समीक्षा के सन्दर्भो के साथ उल्लेखित किया गया है।

शब्दकुंजी– बागवानी, एन.एच.एम.,समग्र विकास, पोषाहार, कृषि के विविध आयाम।

*** शोधछात्र, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन, म.प्र.**

**** प्राध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग; शा.माधव महाविद्यालय, उज्जैन म.प्र.**

प्रस्तावनाः–कृषि देश के आर्थिक विकास की कुंजी है क्योंकि कृषि, आर्थिक विकास की प्रगति के विभिन्न अवयवों में महत्त्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है। अतः कृषि के महत्व को अग्रलिखित तथ्यों के रूप में समझा जा सकता हैः देश की अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास के प्रमुख घटक सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) में सत्र 1950–51 में 55.40 प्रतिशत कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी थी, लेकिन विगत वर्षों में गिरावट देखी गई है जो सत्र 2009–2010 में 14.6 प्रतिशत रही है जबकि चालू वर्ष 2010–11 में 14.2 प्रतिशत का योगदान कृषि क्षेत्र का है। और यह स्थिति देश की अर्थव्यवस्था के विकास को उद्धरित करती है। इसी प्रकार रोजगार की दृष्टि से देश की कुल श्रम शक्ति का लगभग 59.70 प्रतिशत भाग कृषि एवं कृषि से सम्बन्धित उद्योग–धन्धों से अपनी आजीविका को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से संचालित करते है और निजी क्षेत्र का यह सबसे बडा उद्यम है जबकि देश का लगभग 56 प्रतिशत भू–भाग कृषि क्षेत्र का वर्षा पर आधारित है जिससे जोखिम की अधिक संभावनाओं होने के बावजूद भी कृषि लाभ का उद्यम है और इसके अलावा कृषि औद्योगिक विकास के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करती है। *यह* उद्योगों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में कृषि अपनी स्थिति को स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर करती है क्योंकि भारत के विदेशी व्यापार का अधिकांश भाग कृषि से ही जुड़ा हुआ है। वर्ष 2009–10 में देश के निर्यात में कृषि और सम्बन्धित वस्तुओं का अनुपात 9.9 प्रतिशत था। अप्रैल–सितम्बर 2010–11 के दौरान यह घटकर 8.5 प्रतिशत रह गया है। वर्ष 2009–10 के दौरान कृषिगत आयात देश के कुल आयात का 3.7 प्रतिशत था 2010–11 (अप्रैल– सितम्बर) में यह घटकर 3.2 प्रतिशत रहा है। वर्षा की अनिश्चितता के कारण कृषि क्षेत्र में उतार–चढ़ाव की स्थिति होने के उपरान्त भी कृषि का महत्व सर्वाधिक है और कृषि के फलस्वरूप ही वैश्विक स्तर पर भारत की विशिष्ट पहचान है और भारत उन देशों की श्रेणी में शामिल है, जिनका कृषिगत उपजों की वैश्विक आपूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान है संयुक्त राष्ट्र संघ के कृषि एवं खाद्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार 194 कृषिगत उपजों में से 25 उपजों के उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है[1]। अतः इसप्रकार कृषि रोजगार सृजन, खाद्यान्यापूर्ति, पोषण आहार की उपलब्धता, तथा कृषि उपजों के क्षेत्र की उपलब्धियॉ आर्थिक विकास में योगदान प्रदान करती है। इस कारण कृषि को देश की अर्थव्यवस्था का मेरूदण्ड कहा जाये, तो अतिश्योक्ति नहीं होगी।

बागवानी कृषि की एक मुख्य शाखा है। कृषि के क्षेत्र में बागवानी का व्यापक क्षेत्र है और बागवानी को मुख्य तीन भागों में विभाजित किया गया हैः पुष्पोत्पादन, ऑलेरिकल्चरिस्ट तथा फल कृषि विज्ञानी इसकी मुख्य शाखाएॅ है बागवानी में फल, सजावाटी फूल, सुगंधित फूल औषधिये पौधें एवं सब्जियों की खेती तथा उनके फसलोत्पादन प्रबंधन को बागवानी कहा जाता है इस तरह इसमें बहुत – सी फसलों को शामिल किया जाता है। बागवानी का कृषि क्षेत्र में विशिष्ट महत्व है क्योकि देश की कृषि जी.डी.पी. में बागवानी क्षेत्र का 20.00प्रतिशत भाग है जबकि देश की जी.डी.पी. में 4.00प्रतिशत है। आज कृषि में बागवानी को सबसे तीव्र गति से फल रहा क्षेत्र माना जाता है और यह कृषि विकास को प्ररेणा देने वाला एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है जिसे अधिक पौष्टिक भोजन के संबंध में बदल रही हमारी आदत तथा बढ़ती विदेशी मांग द्वारा बल मिला है।

बागवानी ने कृषि के विविध आयामों को विस्तारित कर कृषि के विकास को उन्नयन किया है। इसके महत्व को देखते हुए सभी प्रबुद्धजन एवं सरकार ने इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीति पर विचार कर, पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से कृषि के विकास पर बल देना शुरू कर दिया। इसके तहत शोध कार्य, योजनाओं के कार्यक्रम, एवं नीतिगत योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है, लेकिन हमारे सामने दुःखद बात यह है कि दोषपूर्ण नीति के कारण, आधे से ज्यादा कार्यक्रम असफल हुए है क्योंकि इस क्षेत्र में निवेश की राशि अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा में काफी अल्प है और शोध कार्यो पर व्यय की राशि भी अन्य देशों की तुलना में कम है इसका अंदाजा इस प्रकार लगाया जा सकता है कि भारत में कृषि शोध पर 0.3 प्रतिशत की राशि ही व्यय की जाती है जबकि यही अमेरिका में 4.00 प्रतिशत की राशि खर्च की जा रही है। कृषि पूर्ण लाभ का धंधा बनाने के लिये शोध कार्यो पर बिशेष ध्यान देने की आवश्यकता महसूस की गई है।

इसी संदर्भ में बागवानी विकास की प्रमुख योजना एन.एच.एम है जिसकी शुरूआत 05 मई, 2005 में की गई थी और इसका लक्ष्य बागवानी के समग्र विकास का है। इस प्रकार इसके महत्व को देखते हुए, हमने मिशन की वस्तुपरक स्थिति एवं प्रगति की समीक्षा को इस शोध पत्र में समायोजित किया है।

बागवानीः– बागवानी का शाब्दिक अर्थ फल उद्यान से लगाया जाता है किन्तु विस्तृत रूप में बागवानी क्षेत्र में बहुत सी फसलें शामिल है जैसे– फल, सब्जियॉ, कन्द और मूल फसलें, सुगंधित और औषधीय पौधे, मसाले, चाय, कोको नारियल एवं अन्य बागवानी फसले जो कृषि विविधीकरण को सरल बनाते है जिन्हें नर्सरियों और छोटे खेतों में भी बागवानी की जा सकती है और बागवानी फसले उगाना, आजीविका सुरक्षा सुधारने, रोजगार सृजन बढ़ाने खाद्यान्न सुरक्षा, पोषाहार उपलब्धता एवं मूल्यवर्धन के माध्यम से आय बढ़ाने का विकल्प है बागवानी की एक बड़ी विशेषता यह भी कि यह उसर भूमि को कृषि भूमि में परिवर्तित करती है इस प्रकार बागवानी देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका के साथ ही मानव कार्य क्षमता में वृद्धि कर उन्हें सुखद खुशहाल बनाती है।

बागवानी फसलों का उत्पादन प्रवृति एवं क्षेत्रः– देश में बागवानी फसलों के उत्पादन एवं उनके क्षेत्र विस्तार की प्रवृति को निम्न तालिका द्वारा प्रदर्शित किया है[2]–

तालिका क्र.1
बागवानी फसलों का उत्पादन एवं क्षेत्र

(*क्षेत्रः मिलियन हैक्ट.**उत्पदानः मिलियन टन)

फसल	सत्र							
	2002–03		2003–04		2004–05		2005–06	
	क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन
फल	4.8	49.2	5.1	49.8	5.3	52.8	5.9	54.4
सब्जियॉ	5.9	84.8	6.7	101.4	7.1	108.2	7.2	113.5
मसालें	2.4	3.8	5.2	4.0	3.2	4.9	3.2	5.4
पौधीय फसल	3.1	13.1	3.3	9.4	3.1	10.4	3.2	9.8
सुगंधित पौधें	0.1	0.2	0.2	0.6	0.1	0.7	0.1	0.8
अन्य	0.9	0.9	0.1	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5
योग्य	17.2	152	20.6	165.5	19.2	177.4	20	184.9

(Source: www.nhm.nic.in)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि देश में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के पूर्व बागवानी उत्पादन की स्थिति एवं क्षेत्र विस्तार में बहुत ही धीमी गति से विकास हुआ लेकिन जिस वर्ष मिशन का संचालन किया गया, उस वर्ष 2005–06 में वृद्धि दर्ज की गई है। जिसमें सबसे ज्यादा सब्जियों और फलों के उत्पादन की अधिकता रही है।

देश में बागवानी विकास के लिये बागवानी विकास बोर्ड की स्थापना सन 1984 में की गई थी जिसके फलस्वरूप वैश्वीकरण के समय से बागवानी की महत्वत्ता अधिक देखी गई जिसके कारण बागवानी के समग्र विकास के उद्देश्य से राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरूआत दसवीं पंचवर्षीय योजना में की गई जिसके परिणामतः इस क्षेत्र में तीव्रतः की वृद्धि देखी गई जो एक तालिका से स्पष्ट होता है–

तालिका क्र.2
बागवानी फसलों का उत्पादन एवं क्षेत्र

(मिशन के दौरान की स्थिति)

वर्ष	क्षेत्र*	उत्पादन**
2006–07	19.4	191.8
2007–08	20.2	211.7
2008–09	20.7	214.7
2009–10	20.8	222.9

(स्रोतः वार्षिक रिपोर्ट,2010–11 कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली (नोटः–*क्षेत्रः मिलियन हैक्ट, **उत्पादनः मिलियन टन)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि मिशन के दौरान देश में बागवानी फसलों कें उत्पादन एवं उनके क्षेत्रफल में लगातार अभिवृद्धि दर्ज हुई वर्ष 2009–10 में फलों का उत्पादन 72.3 मिलियन टन, 6.5 मिलियन हैक्ट. क्षेत्र में हुआ और सब्जियॉ 7.9 मिलियन हैक्ट.क्षेत्र में133.5 मिलियन टन का उत्पादन, मसाले 2.46 मिलियन हैक्ट. क्षेत्र में 4.02 मिलियन मैट्रिक टन का उत्पादन हुआ है इस प्रकार बागवानी फसलों का उत्पादन क्षेत्र के सम्बन्ध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभरती हुई तस्वीर सामने आ रही है[3] ।

बागवानी विकास कार्यक्रमः– देश में बागवानी विकास, कृषि एवं सहकारिता विभाग के विकासात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से किया जा रहा है राष्ट्रीय बागवानी मिशन, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में समेकित बागवानी विकास प्रौद्योगिकी मिशन, लघु सिंचाई, राष्ट्रीय बांस मिशन, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड़ की स्कीमें एन.एच.एम. और नारियल विकास बोर्ड़ द्वारा नारियल समन्वय पर प्रौद्योगिकी मिशन सहित समेकित नारियल विकास और इसके अलावा मानव संसाधन विकास हेतु राष्ट्रीय स्तर की 13 ऐजेंसियों के माध्यम से कार्यों का संचालन किया जा रहा है।

राष्ट्रीय बागवानी मिशन(एन.एच.एम.):–राष्ट्रीय बागवानी मिशन केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित एकीकृत कार्यक्रम (स्कीम) है जो कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय द्वारा दसवीं पंचवर्षीय के दौरान 5 मई 2005 से सभी देश के 18 राज्यों और 3 शासित प्रदेश और 371 जिलों में शुरूआत की गई है। यह मिशन सभी की सक्रिय भागीदारी के साथ अग्र तथा पृष्ठ सम्पर्क सुनिश्चित करते हुए बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए देश में इस मिशन का संचालन कलस्टर एप्रोच से किया गया है

किन्तु यह सिक्किम सहित 8 पूर्वोत्तर राज्यों तथा जम्मू–कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखण्ड राज्यों को छोड़कर इस मिशन का क्रियान्वयन सम्पूर्ण भारत में किया जा रहा है। इस मिशन को विस्तारित करते हुए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में इसे सौ प्रतिशत की सहायता करता जिसमें 85 प्रतिशत का योगदान केन्द्र सरकार और शेष 15 प्रतिशत की सहायता राशि राज्य सरकारें उपलब्ध करवाती है। जिसमें हितग्राहियों को 70 प्रतिशत भौतिक रूप से और 30 प्रतिशत आर्थिक मदद का प्रावधान है।

मिशन के उद्देश्यः– राष्ट्रीय बागवानी मिशन के प्रमुख उद्देश्य निम्न है[4]–

1 .प्रत्येक राज्य/क्षेत्र के तुलनात्मक लाभ और उसके भिन्न कृषि–जलवायु विशेषताओं के अनुरूप क्षेत्र आधारित भिन्न कार्यनीतियों के माध्यम से बागवानी क्षेत्र का समग्र विकास करना, जिसमें अनुसंधान, प्रौद्योकिकी संवर्धन, विस्तार, कटाई–पृष्ठ प्रबंधन, प्रसंस्कारण एवं विपणन शामिल है।

2. बागवानी उत्पादन में वृद्धि करना, पोषण सुरक्षा में सुधार और कृषि परिवारों की आय में सर्मथन प्रदान करना।
3. बागवानी विकास हेतु योजना एवं कार्यक्रमों के मध्य अभिसरण तथा समन्वय स्थापित करन।
4. पंरपरागत विवेक रहित और आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान के मिश्रण के माध्यम से बागवानी विकास हेतु प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना एवं विकसित कर प्रसार करना।

5. कुशल तथा अकुशल व्यक्तियों हेतु रोजगार सृजन अवसरो को उत्पन्न करना, विशेष रूप से बेरोजगार व्यक्तियों हेतु।

कार्यनीतिः–1. उत्पादन, कटाई–पृष्ठ प्रबंधन, प्रसंस्करण और उत्पादकों को उचित प्रतिफल सुनिश्चित करने के लिए विपणन को कवर करने वाली सिरे से सिरे की एक समग्र सोच को अपनाना

2. उत्पादन कटाई–पृष्ठ प्रबंधन तथा प्रसंस्करण हेतु अनुसंधान एवं विकास प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना।
3. उत्पादन में वृद्धि के लिए संचयन करना
4. सभी स्तरों पर क्षमता निर्माण तथा मानव संसाधन विकास को बढ़ावा देना।

एन.एच.एम. की संरचना एवं संघटनः– मिशन के संघटन और संरचना को ग्राफ के द्वारा बताया गया जो निम्न प्रकार है क्योंकि मिशन का संचालन एक कलस्टर के माध्यम से किया जाता है जिसका आधार त्रिस्तरीय है

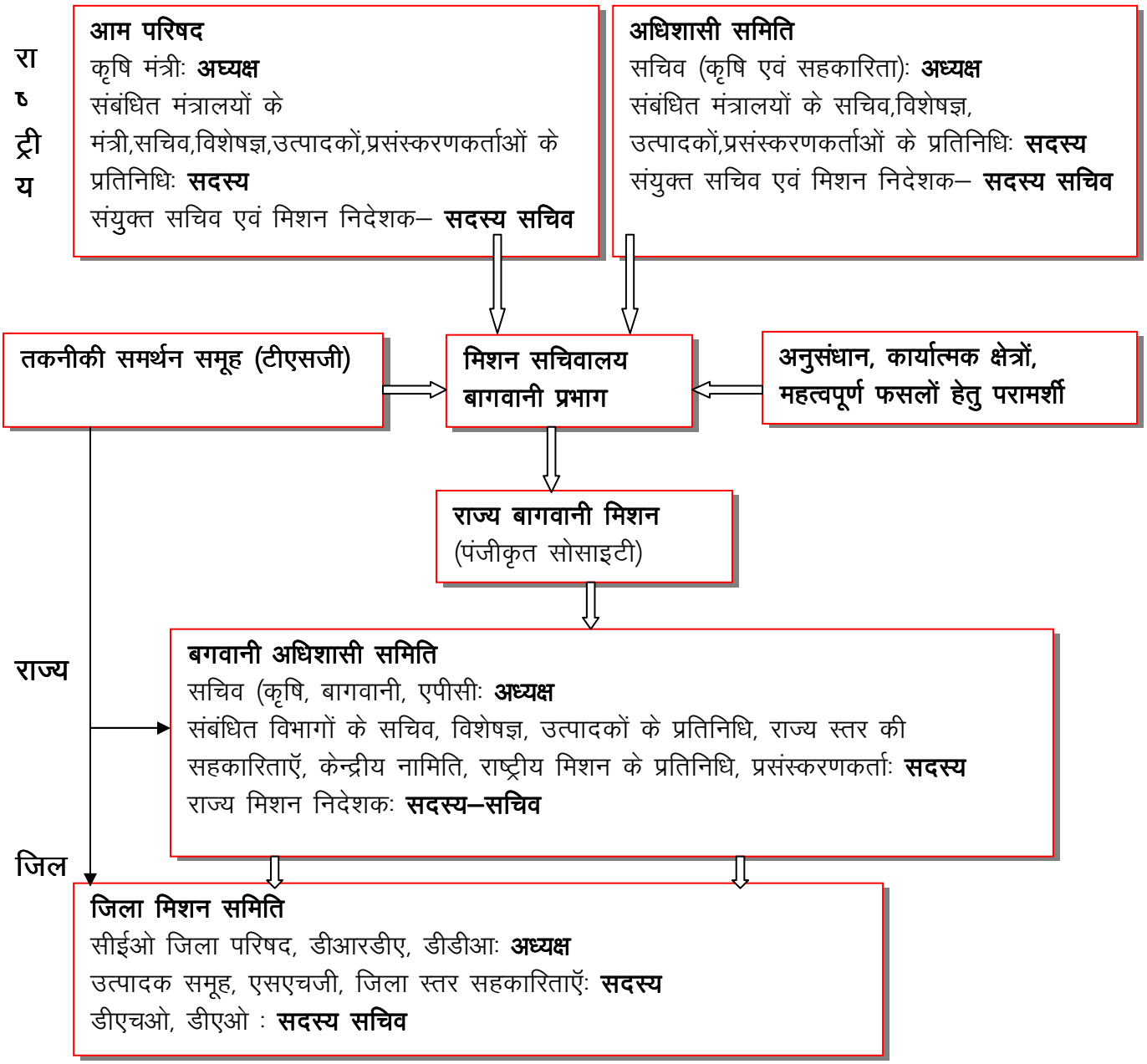

एन.एच.एम की भौतिक प्रगतिः– मिशन की भौतिक प्रगति का संक्षिप्त ब्यौरा नीचे सारणी में दिया गया है–

सारणी क्र.3

एन.एच.एम के अंतर्गत भौतिक प्रगति

(क्षेत्र– लाख हैक्टेयर में)

क्र.सं.	मद	2005–06 से2009–10	2010–11,जनवरी 11 तक
1	नर्सरियॉ(संख्या)	2192	55
2	विस्तारित क्षेत्र	16.51	2.10
3	जराग्रस्त पौधें का पुनरूद्धार	2.78	0.37
4	जैविक कृषि	1.37	0.05
5	समेकित कृषि प्रबंधन व पोषक तत्व	7.53	1.04
6	पैक हाउस (संख्या)	1091	546
7	शीत भण्डारण (संख्या)	367	43
8	मण्डी (संख्या)	172	9
9	मोबाईल/प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट	264	69

स्रोतः वार्षिक रिपोर्ट:2010–11 कृषि मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि देश में एन.एच.एम के तहत बागवानी विकास में काफी रूप में भौतिक वृद्धि दर्ज की गई जिसमें बागवानी क्षेत्र के विस्तार में सत्र 2010–11 में2.10 लाख हेक्टेयर भूमि को कवर किया गया है। इसी प्रकार जैविक कृषि के अंतर्गत इसी वर्ष 0. 05 लाख हैक्ट. पर जैविक कृषि को बढ़ावा दिया गया।

वित्तीय प्रगतिः– मिशन की वित्तीय प्रगति में वर्ष 2005–06 से 2009–10 तक 4303.12 करोड़ रूपए की धनराशि प्रदान की गई है जिसमें से 4125.43 करोड़ रूपए व्यय हुए है और वर्ष 2010–11 में 1061.98 करोड़ रू. प्रदान किये गए है और 801.38 करोड़ रू. स्कीम के कार्यान्वयन निर्मुक्त हुए है।

निष्कर्षः कृषि देश की अर्थव्यवस्था के विकास में रीड़ की हड्डी साबित हो रही है क्योंकि देश की कार्यशील जनसंख्या सर्वाधिक कृषि क्षेत्र से ही अपनी अजीविका को सुरक्षित करता है जितनी की अन्य क्षेत्रो से नही करता है इसके साथ कृषि का क्षेत्र वृहद होने के कारण इसमें सम्भावना और अधिक बढ़ जाती है इसक दूसरा क्षेत्र बागवानी है जो कृषि क्षेत्र को और अधिक विस्तारित करता है साथ ही यह विविधीकरण एक विकल्प है और देश में बागवानी विकास की अपार संभावनाए है। बागवानी की महत्वता वर्तमान परिस्थितियों में और अधिक बढ़

जाती है जिसमें सबसे ज्यादा महत्व पोषाहार, जैविक कृषि, रोजगार सृजन, कृषि भूमि के विस्तार के साथ ही कृषकों की आय वृद्धि का एक विकल्प है जिससे कृषकों के जीवन स्तर को उच्च करना है और यह देश की कृषि क्षेत्र के समग्र विकास के लक्ष्य प्राप्ति में सहायक सिद्ध होता है देश में बागवानी विकास की प्रमुख स्कीम राष्ट्रीय बागवानी मिशन है जिसने बागवानी विकास को उच्चारित किया है इससे बागवानी की स्थिति पहले से अपेक्षित वृद्धि की है यह अभी अपने वंचित पूरे लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ है इसके लिये आवश्यक है कि कृषको को जागरूक किया जाए और गांव–गांव में चौपाल लगाकर मिशन की जानकारी एवं सहायता प्रदान करने के साथ पंचायत स्तर पर ट्रेनिंग दी जाए और समय समय पर मिशन के कार्यकारिणी क्षेत्र को लोचनीय बनाया जाय, और इसके फलस्वरूप मिशन बागवानी विकास में एक रामबाण के रूप में साबित हो सकें ।

संदर्भः

1–प्रतियोगिता दर्पण(अतिरिक्तांक)''भारतीय अर्थव्यवस्था'' वर्ष–2011, आगरा

2-www.nhm.nic.in)

3–वार्षिक रिपोर्ट:2010–11 कृषि मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।

4–राष्ट्रीय बागवानी मिशन,'' प्रचालनात्मक दिशा– निर्देश, अप्रैल–2010, कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली

****